557वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 557वीं बैठक दिनांक 03/03/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 8585/2021 Shri Harendra Singh Bhadauria S/o Shri Kishore Singh Bhadauria, Thatipur, Dist. Gwalior Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.450 ha. (43000 cum per annum) (Khasra No. 2269), Village - Bilhati, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2269), Village - Bilhati, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior (MP) 1.450 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09/08/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरेन्द्र सिंह भदौरिया और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ. आर.के. पाण्डेय उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के उत्तर दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर एक नहर स्थित है जो एम.एम.आर., 1996 के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर) की सीमा के अंदर है अतः 10 मीटर का सेड–बेक छोडे जाने हेतु समिति ने निर्देशित किया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया

गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (प्राथमिक विद्यलाय बिलहेटी में कार्य तथा कोविड हेतु मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण इत्यादि) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । समिति प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि जन सुनवाई में धूल के कारण खेती प्रभावित होने की बात उठाई गई है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अभी कोई कार्य नहीं किया गया है अतः यह समस्या क्षेत्र में स्थित अन्य खदानों के कारण हो रही होगी । समिति ने परियेाजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो । पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ पुनरीक्षित जल खपत योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर एक नहर है, अतः 10 मीटर का सेड–बैक (नॉन माईनिंग क्षेत्र)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 43,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर एक नहर के कारण 10 मीटर का सेड–बैक (नॉन माईनिंग क्षेत्र) छोड़ा जायेगा ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.79 लाख एवं रिक्ररिग 03.37 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.24 लाख :–

क्रं.	सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
01	ग्राम बिल्हेटी के प्राथमिक विघालय में 10 नग टेबल व बेंच की प्रदान किया जाएगा।	20,000
02	ग्राम बिल्हेटी में प्राथमिक विघालय की दीवारों में पेंटिंग कराया जाएगा।	15,000
03	ग्राम बिल्हेटी व प्राथमिक विघालय में 04 नग सोलर लाईट व 50 नग पौधे का वितरण किया जाएगा।	49,000
04	मजदूरों एवं ग्रामवासियों को 200 नग मास्क और दस्ताने एवं 10 लीटर सैनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।	10,000
05	सी.ई.आर. के तहत खदान श्रामिकों को ''उज्जवला योजना'' के तहत 10 सोलर कुकर/गैस सिलेंडर का वितरण।	30,000
ईएमपी में वृक्षारोपण, चिकित्सा जांच और जल छिडकाव प्रणाली को शामिल किया गया है।		
	योग	1,24,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1750 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, बबूल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	610
2	परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, महुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	450
3	बिलहेटी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, मुनगा, आम, अमरूद।	660
6	विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार।	30
		योग	1750

2. <u>Case No 8570/2021 Shri Kedar Singh Yadav S/o Shri Bheemkam Singh Yadav, Ward No. 05, Veerendra Oil Mill, Mai Road, Jaura, Dist. Morena, MP - 476221 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.470 ha. (32000 cum per annum) (Khasra No. 2203, 2208), Village - Bilhati, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior (MP).EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2203, 2208), Village - Bilhati, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior (MP) 1.470 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 504वीं दिनांक 23/07/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री केदार सिंह और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ. आर.के. पाण्डेय उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह रोड़ क्षेत्र में कार्यरत एक अन्य खदान हेतु पहुच मार्ग हैं फिर भी वे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 मीटर का सेड बेक छोडने हेतु तैयार है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर रहे है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य ((प्राथमिक विद्यलाय बिलहेटी में कार्य तथा कोविड हेतु मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण इत्यादि)

किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । समिति प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि जन सुनवाई में धूल के कारण खेती प्रभावित होने की बात उठाई गई है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अभी कोई कार्य नहीं किया गया है अतः यह समस्या क्षेत्र में स्थित अन्य खदानों के कारण हो रही होगी । समिति ने परियेाजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो । पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित 10 मीटर का सेट–बेक के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ पुनरीक्षित जल खपत योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 32,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.05 लाख एवं रिक्करिग 03.25 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.10 लाख :–

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
प्राथमिक विघालय बिल्हेटी के विघार्थियों के लिए 5 खेल किट की व्यवस्था की जायेगी।	10,000/–
प्राथमिक विघालय बिल्हेटी के विघार्थियों के लिए एक कम्प्यूटर सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।	30,000
ग्राम बिल्हेटी में एक हैडपंप की स्थापना कराई जाऐगी ।	40,000/–
सी.ई.आर. के तहत खदान श्रामिकों को ''उज्जवला योजना'' के तहत 10 सोलर कुकर/गैस सिलेंडर का वितरण।	30,000/–
(आगामी एक वर्ष तक) योग	**1,10,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1764 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	546

परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, महुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	600
बिलहेटी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	600
विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार।	24
	योग	1764

3. <u>Case No 8478/2021 Shri Shailendra Singh, AM 111, Deendayal Nagar, Distt Gwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,50,005 Cum per annum) (Khasra No. 4175), Village – Parsen, Tehsil – Gwalior, Distt. Gwalior (M.P.)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 4175), Village – Parsen, Tehsil – Gwalior, Distt. Gwalior (M.P.) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 497वीं दिनांक 05/04/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार डॉ. आर.के. पाण्डेय उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान पहाड़ पर स्थित है जिसके चारो ओर अन्य खदानें कार्यरत है, खदान के पूर्वी एवं उत्तर–पूर्व क्षेत्र एक तालाब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। खदान के पूर्वी क्षेत्र से एक कच्चा रास्ता खदान से होकर निकल रहा है, जिसके संदर्भ में पी.पी. ने बताया कि यह कच्चा रास्ता क्षेत्र में कार्यरत अन्य खदानो द्वारा निकलने हेतु बना लिया गया है, जब हमारी खदान चालू होगी तब यह पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान रास्ते का उपयोग करते हुए अपना मिनरल निकालेगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने निर्देशित किया कि फेरो की सख्या कम करने के उददेश्य से खनिज का परिवहन 40 टन भार क्षमता के वाहनो का उपयोग किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । समिति ने परियेाजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो । पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की खनिज परिवहन हेतु 40 टन की क्षमता के वाहनो का उपयोग किया जायेगा ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,50,005 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खनिज परिवहन हेतु 40 टन की क्षमता के वाहनो का उपयोग किया जाये ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.87 लाख एवं रिकरिग 10.07 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.30 लाख :–

क्रं.	सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
01	ग्रामपंचायत को 500 नग मास्क एवं 10 लीटर सैनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।	5,000
02	प्राथमिक विघालय पारसेन में 01 सोलर लाइट एवं 01 हैण्डपम्प उपलब्ध कराया जाएगा।	50,000
03	सी.ई.आर. के तहत खदान श्रामिकों को ''उज्जवला योजना'' के तहत 25 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।	75,000
i	सडक का निर्माण।	इएमपी में पहले से ही शामिल किया गया है।
ii	जल छिडकाव प्रणाली की सुविधा की व्यवस्था कराई जाये।	
iii	ज्यादा से ज्यादा पेड लगाए।	
	(आगामी एक वर्ष तक) योग	**1,30,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5000 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	2000
2	परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, महुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	1000
3	पारसेन ग्रामवासियों में वितरण	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	1950
4	विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार।	50
		योग	**5000**

4. <u>प्रकरण क्रमांक 9010/2022 – श्रीमती कविता दाँगी, पीपल्यकलॉ, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 96/6 रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–7030 मी.^{3}, ग्राम हिम्मतगढ़, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 96/6 रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम हिम्मतगढ़, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कविता दॉगी ऑन लाईन/आफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 176 दिनांक 03/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 60 मीटर पर एवं पूर्व दिशा में 235 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 98 मीटर पर प्राकृतिक नाला, दक्षिण–पूर्व दिशा में 459 मीटर पर आबादी है तथा 440 मीटर पर जल भराव क्षेत्र हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरन परियोजना प्रस्तावक ने वताया कि खनिज उत्खनन के दौरान आंवटित क्षेत्र में कोई पेड. काटे जाने का प्रस्ताव नही है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 7030 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.16 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में

चितावलिया (हिम्मतगढ़)	**ग्राम चितावलिया (हिम्मतगढ़) स्थित माध्यमिक स्कूल मे पीपी द्वारा एक हैंडपंप (प्रोटेक्शन वाल और रिचार्ज पिट के साथ) लगाया जाएगा I**	**70,000**
	योग	**70,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1220 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण योजना		
प्रस्तावित वृक्षारोपण	**पौधों की प्रजातियां**	**संख्या**
बैरियर जोन	नीम , जंगल जलेबी ,रीठा, सीताफल , चिरोल , खमेर तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	320
हिम्मतगढ़ ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली , आवलाँ सीताफल ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	500
पश्चिम दिशा की ओर स्थित प्राकर्तिक नाले की दोनों तरफ	खस घास , कटंग बाँस	150
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	जंगल जलेबी ,करंज,कदम ,चिरोल तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	250
	योग	1220

5. <u>प्रकरण क्रमांक 9011/2022 – श्री सुनील कुमार खटीक, वार्ड नं. 12 पुराना बाजार, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 129/1/3 रकबा 1.214 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–11,760 मी.^{3}, ग्राम – नयागाँव तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 129/1/3 रकबा 1.214 हेक्टेयर, ग्राम – नयागॉव तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पर स्थित है।

557वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2022

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील कुमार खटीक ऑन लाईन/आफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 2919 दिनांक 09/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर–पूर्व दिशा में 200 मीटर पर आबादी, उत्तर–पश्चिम दिशा में 175 मीटर पर रोड़, पूर्व क्षेत्र में 100 मीटर पर कच्चा रोड तथा दक्षिण क्षेत्र में 300 मीटर पर शेड है । प्रस्तुतीकरण दौरान यह पाया गया कि आंवटित लीज क्षेत्र में एक पुराना पिट मौजूद है जिसके संदर्भ में पीपी ने बताया कि इसी स्थिति में हमको लीज आंवटित की गई है तथा पिट 2015 से है एवं लीज 2021 में मिली है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –11,760 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20. लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
नयागांव	ग्राम नयागांव स्थित माध्यमिक स्कूल मे पीपी द्वारा निम्नानुसार वस्तुयें प्रदान किये जावेंगे ;- 1). 40 टेबल और कुर्सी सेट (2000 रुपए प्रति सेट)	80,000
	2). 2 कंप्यूटर सिस्टम (20,000 रुपये प्रति कंप्यूटर)	40,000
	योग	1,20,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण योजना		
वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियां	**संख्या**
खनि पट्टे की पूर्वी बैरियर जोन में	नीम , जंगल जलेबी ,रीठा , सीताफल, चिरोल , खमेर तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	**200**
नयागांव ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली , आवलाँ, सीताफल ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	**1000**
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	जंगल जलेबी ,करंज,कदम ,चिरोल तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	**300**
	योग	**1500**

6. <u>प्रकरण क्रमांक 9017/2022 – मेसर्स सिटी होम डेव्हलपर्स, पार्टनर श्री अनुराग पाठक, मकान न. 228, प्रगति भवन, कोटेश्वर कॉलोनी, वार्ड न. 10, कोटेश्वर मंदिन के सामने, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 661, 662, 664, 665, 673, 674, 710 रकबा 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–60,643 मी.^{3}, ग्राम – करबास तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 661, 662, 664, 665, 673, 674, 710 रकबा 2.50 हेक्टेयर, ग्राम करबास तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक **श्री अनुराग पाठक** ऑन लाईन/ऑफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 4939 दिनांक 03/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 54 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 345 मीटर पर नाला होना परिलक्षित हो रहा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 60,643 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.52 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
करवास	ग्राम करवास स्थित आंगनवाड़ी तथा माध्यमिक स्कूल मे पीपी द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :- 1). आंगनवाड़ी मे एक वर्ष तक ''पोषण आहार'' का वितरण	1,00,000/-
	2). माध्यमिक स्कूल मे 2 कंप्यूटर सिस्टम तथा 2 प्रिंटर का वितरण (30,000 रुपये प्रति सेट)	60,000/-
	योग	1,60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

पौधों की प्रजातियां	संख्या	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान
बैरियर जोन	नीम , जंगल जलेबी ,रीठा , चिरोल , सीताफल , खमेर तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	900
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	जंगल जलेबी ,करंज,कदम ,चिरोल तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	500
करवास ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली , आवलाँ,सीताफल ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	1600
	योग	3,000

7. Case No 9013/2022 M/s Agrawal Builders & Colonizers Co., Shri Sagar Agrawal, Partner, The Sagar E2/4, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sagar Prime Residential Towers Project at Village - Bawadia Kalan, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Sagar Prime Residential Towers Project at Village - Bawadia Kalan, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) with 189 no of flats [Total Plot Area = 1.164 ha., Total Built-Up Area = 33716.04 Sq. Mtrs At **Khasara No 140/1/1/ड, 140/1/2/ड, 140/1/2/ख, 140/1/1/1क,140/1/2/घ, 140/1/2/झ,140/1/2/ञ, 140/1/2/ट,140/1/2/ठ, 140/1/2/च P. H. No. 18 , BMC Ward No. 52 (Zone No. 13) Gram – Bawadia Kalan , Tehsil Kolar , Distt. Bhopal (M.P.),** hence project requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and recommendation on the project.

The case was presented by the PP and their consultant in 557th SEAC meeting dated 03.03.2022 and during presentation following details were provided.

It is a residential project (07 blocks and 189 Flats) with provision of green features like solar power plant (15 KW), MBBR technology based STP (125 KLD), MSW management, energy conservation measures, rain water harvesting system etc. PP has obtained permission from BMC for water supply, sewage disposal and MSW disposal.

S. No.	Item	Details
1.	Name of the project	Commercial project with 189 flats ., Total Built-up Area = 33716.04 Sq. Mtrs
2.	S. No. in schedule	The project is categorized as 'B-1' under item 8 (a) of Schedule -Gazette Notification dated Sep 14th, 2006 and subsequent amendments issued by MoEF, New Delhi on 01.12.09 and 04.04.2011.
3.	Proposed capacity / area / length / tonnage to be handled / command area / lease area / number of wells to be drilled	The land use of the proposed project is as under:- Residential complex [Total Plot Area = 1.164 ha ., Total Built-up Area = 33716.04 Sq. Mtrs Use – Residential Complex with 189 flats Structure - 2 Podium + + 7 Floors 7 Floors
4.	New / Expansion / Modernization	New
5.	Existing Capacity/Area etc.	It is green field project
6.	Category of Project i.e. 'A[1] or 'B'	'B'
7.	Does it attract the General condition? If Yes, please specify.	No
8.	Does it attract the Specific condition? If Yes, please specify.	No

<table>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td>Plot/Survey/Khasra No.</td><td>Khasara No 140/1/1/ड, 140/1/2/ड, 140/1/2/ख, 140/1/1/1क,140/1/2/घ, 140/1/2/झ,140/1/2/ञ, 140/1/2/ट,140/1/2/ठ, 140/1/2/च P. H. No. 18 , BMC Ward No. 52 (Zone No. 13)</td></tr>
<tr><td>Village</td><td>Gram – Bawadia Kalan ,</td></tr>
<tr><td>Tehsil</td><td>Tehsil Kolar , Distt.</td></tr>
<tr><td>District</td><td>Bhopal (M.P.)</td></tr>
<tr><td></td><td>State</td><td>Madhya Pradesh</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Nearest railway station/airport along with distance in kms.</td><td>Rani Kamlapati Railway Station – 7km
Bhopal Airport – 23 km.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Nearest Town, City, District Headquarters along with distance in kms.</td><td><table><tr><td>Nearest</td><td>Name</td><td>Distance</td></tr><tr><td>City</td><td>Bhopal</td><td>Within Municipal Area</td></tr><tr><td>District Headquarters</td><td>Bhopal</td><td>Within Municipal Area</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Village Panchayats, Zilla Parishad, Municipal Corporation, Local body (complete postal addresses with telephone</td><td>Bhopal Municipal Corporation</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Name of the applicant</td><td>M/S Agrawal Builders & Colonizers
E-4/231, Arera Colony, Bhopal (MP)
462018</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Registered Address</td><td>E-4/231, Arera Colony, Bhopal (MP)
462018</td></tr>
<tr><td rowspan="6">15</td><td>Address for correspondence:</td><td>E-4/231, Arera Colony, Bhopal (MP)
462018</td></tr>
<tr><td>Name</td><td>Mr. Shri Sagar Agrawal</td></tr>
<tr><td>Designation (Owner/Partner/CEO)</td><td>Partner</td></tr>
<tr><td>Address</td><td>E-4/231, Arera Colony, Bhopal (MP)
462018</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>architectureab@thesagar.in</td></tr>
<tr><td>Telephone No.</td><td>0755-2460107</td></tr>
<tr><td></td><td>Fax No.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up?
(a) Name of the Court
(b) Case No.
(c) Orders/directions of the Court, if any and its relevance with the proposed project.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>17</td><td>List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.</td><td><table><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

#	Items	Details
1	Proposed Project	Sagar Prime - Residential Complex
2	Dwelling Units	Total Number of Flats -: 189 no. (HIG & MIG Flats - 115+ 48 = 163 no, LIG – 10 nc
3	Total Water Requirement	129 KLD
4	Net Fresh Water Requirement	86 KLD
5	Total Waste Water Generation	116 KLD
6	Power Requirement	2923 KVA
7	Backup Power facility	125 KVA of DG set
8	Solid Waste generation	528 Kg per Day
9	Height of buildings	18 M
10	Front MOS	7.5
11	Rear MOS	6.0
12	Width of main assess	12 M
13	Parking area with circulation	12800 Sq mt
14	Parking Number	220
15	Landscaped Green Area	1290 Sq mt

Name of the consultant	Creative Enviro Services 42 Doorsnchar Colony E 8 Gulmohar Bhopal (MP)
SR. No. in Nabet/QCI List	29

During discussion it was suggested by committee that Griha Rating shall be obtained by PP and some electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy. After presentation and discussion PP was asked to submit response on following:

1. Regarding revised CER programme wrt proposed project.
2. Revised EMP as suggested by committee.

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016 and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project propoenent shall obtained Griha rating for this project and provide electrical charging points for E-Vehicles to promote clean energy.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. Total Power Requirement for the proposed project is 2923 KVA
v. Diesel power generating sets proposed (Capacity – 125 KVA as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG Sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Low sulphur diesel shall be used on DG Sets. The location of the DG sets may be decided with in consultation with MP Pollution Control Board.
vi. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well

as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vii. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

viii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

ix. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

x. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

xi. The gaseous emission from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality, the ventilation provisions as per National Building Code of India shall be provided.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. Total fresh water use shall not exceed 86 KLD, and treated water available for reuse will be 105 KLD.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be monitor and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water

available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. PP should explore the possibility of providing water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. Rain water harvesting recharge pits 2 nos. shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xiii. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xiv. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering, if any.

xv. Sewage shall be treated in the STP 125 KLD with tertiary treatment. The treated effluent from STP of 105 KLD from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. The 56 KLD treated surplus water shall only be disposed in to municipal drain after having approval from the competent authority.

xvi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xvii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odor problems from STP.

xviii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and

Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets (Capacity– 125 KVA), noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

iv. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed in meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/local building bye-law's requirement, whichever is higher.

v. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power.

VI. Waste Management

i. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

ii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (528 KGD) shall be segregated into wet garbage and inert materials.

iii. E-waste (180 Kg/Year) should properly dispose of through authorized vendors.

iv. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

v. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the MP Pollution Control Board.
vi. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
vii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
viii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
ix. Used CFLs, TFLs and other e-waste should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid contamination.

VII. Green Cover

i. Not tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department.
ii. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the plantation scheme minimum of 130 no's of trees to be planted. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
iii. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
iv. The 1290 sq. meters (12%) of total area shall be provided for green belt development with 130 no. as per the details provided in the project document.
v. As proposed, the green belt development / plantation activities should be completed within the first three years of the project and the proposed species should also be planted in consultation with the forest department.
vi. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points.
   d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Parking's for 220 Nos. as proposed by PP over area of 12800 sq mtrs (Podium : 6400 sq.m, Stilt : 6400 sq.m)

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation, provisions as per National Building Code of India shall be provided.

iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporation Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
ii. In the EMP, PP has proposed Rs. 103.30 lakh as capital cost and Rs. 28.775 lakh/year for recurring expenses in the operation phase.
iii. Under CER different activities the PP proposed Rs. 35.00 Lakh for following activities .

PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY			
SN	**Plan**	**Area of Activity**	**Budgetary provisions (Rs in lacs)**
1	Health awareness progarmme twice in year (Rs 50,000/-) for selected villages for one time	In 10 villages surrounding to Bhopal	Rs 10 Lacs
2	Adaptation of school with provision of furniture (50 table and chairs in each class room) , Fans at each rooms, Library, Up gradation of toilets (4 for girls and 04 for boys), Drinking water facility (RO)- 04 numbers), sport ground, and boundary wall	School of village in dist Bhopal (MP)	Rs 20 Lacs
3	Adaptation of Tiger	At Van Viahr Bhopal, through Director Van Vihar Bhopal	Rs 2 Lacs
4	Provision of essential facility like utensil, fans, mattresses, clothes other house hold facilities in consultation with the operator of old age home for needful requirement	Old age homes located at Bhoapl viz, Apna Ghar, Anand Dham etc	Rs 3 Lcas
	Total		**35 Lacs**

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The

copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

8. <u>प्रकरण कमांक 9014/2022 – श्रीमती अंजू शर्मा, निवासी चौधरी वारी हाऊस, ग्राम बडफरा, तहसील अंबाह जिला मुरैना (म.प्र.) स्वाईल क्वेरी, खसरा नं. 640, 693/2, 641, रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वाईल–2,000 मी.^{3}, ग्राम बडफरा, तहसील अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण स्वाईल उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 640, 693/2, 641, रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वाईल–2,000 मी.3, ग्राम बडफरा, तहसील अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजू शर्मा ऑन लाईन/ऑफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में

संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 482 दिनांक 03/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 130 मीटर पर रोड़ तथा उत्तर पूर्व दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रोड है । प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बाताया कि ब्लास्टिग प्रस्तावित नही है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन् नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नही की जावेगी । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि
  - ➢ लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ है, जिसे नहीं काटा जायेगा।
  - ➢ लीज क्षेत्र से चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी ।
  - ➢ 02 मीटर गहराई तक ही उत्खनन् किया जावेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल – 2,000 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.36 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रूपये में
सरकारी कार्यक्रम ''पोषण आहार'' में वित्तीय सहायता	15,000
महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लब्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण	5,000
योग	**20,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण स्थान	पौधों की प्रजातियां	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि।	360
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला, पुत्ररनजीवा, मोलश्री आदि।	90
विद्यालय	नीम कचनार, महुआ, अचार अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	50
ग्राम बड़फरा के आंगनवाड़ी केंद्र में वितरण हेतु	नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला, पुत्ररनजीवा, गूगल मोलश्री आदि।	700
	योग	1200

9. <u>प्रकरण क्रमांक 9015/2022 – श्री मुनेश कुमार शर्मा, ग्राम मुड़ियाखेड़ा, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) स्वाईल क्वेरी, खसरा नं. 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वाईल–2,025 मी.^{3}, ग्राम मुरैनागॉव तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण स्वाईल उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम मुरैनागॉव तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुनेश कुमार शर्मा, ऑन लाईन/ऑफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1571 दिनांक 16/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 295 मीटर पर तथा उत्तर दिशा में 325 मीटर पर रोड़ तथा उत्तर पूर्व दिशा में

350 मीटर तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 228 मीटर पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बाताया कि ब्लास्टिग प्रस्तावित नही है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन् नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नही की जावेगी । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि
  - ➢ लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ है, जिसे नहीं काटा जायेगा।
  - ➢ लीज क्षेत्र से चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी ।
  - ➢ 02 मीटर गहराई तक ही उत्खनन् किया जावेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल – 2,025 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.90 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रूपये में
सरकारी कार्यक्रम ''पोषण आहार'' में वित्तीय सहायता	25,000
गॉव के स्कूल में बेंच का वितरण (04 बेंच)	10,000
महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लब्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण	5000
योग	**40,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित नियत स्थान	**पौधों की प्रजातियां**	**मात्रा (संख्या में)**
बैरियर जोन	**नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि।**	**520**

परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	**नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला,** पुत्रंरनजीवा, **मोलश्री आदि।**	**370**
विद्यालय	नीम **कचनार**, महुआ, **अचार अमलतास** एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	**50**
ग्राम मुरैनागांव के आंगनवाड़ी केंद्र में वितरण हेतु	**नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला,** पुत्रंरनजीवा, **गूगल मोलश्री आदि।**	**1460**
	योग	**2400**

10. <u>प्रकरण क्रमांक 9016/2022 – श्री सुखदेव डावर, 45 महॉवीर नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 21/1पेकी, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन क्वेरी –10,000 मी.^{3}, ग्राम दामखेड़ा, तहसील झिरनिया, जिला खरगौन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित खसरा नं. 21/1पेकी, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन क्वेरी –10,000 मी.3, ग्राम दामखेड़ा, तहसील झिरनिया, जिला खरगौन (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुखदेव डावर ऑन लाईन/ऑफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 6081 दिनांक 07/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 380 मीटर पर रोड़ एवं 180 मीटर पर नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में एक नीम का पेड है जिसे काटा जायेगा तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त नीम के ही पेड़ लगाये जायेगे। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –10,000 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.49 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 04.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.65 लाख :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
	- ग्राम पंचायत दामखेड़ा के पंचायत भवन की मरम्मत तथा पुताई का कार्य	50,000/-
	- ग्राम मुल्तान, कसरावद रोड के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में पौधों की सिंचायी के लिए ड्रिप इरीगेशन तकनीक से पानी की व्यवस्था कराई जावेगी	15,000/-
	योग	**65,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2450 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, सफेद कैस्टर, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
2	परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	करंज, सप्तपर्णी , चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा , नीम, सिस्सू , कटंग बांस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री–गार्ड के साथ	800
3	ग्राम दामखेड़ा के विद्यालय परिसर में	पीपल करंज, पुत्रंजीवा, मोलश्री, चिरोल, नीम, कदम्ब, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	310
4	ग्राम दामखेड़ा में ग्रामवासियो एवं पंचायत से परामर्श लेकर	पुत्रंजीवा,मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मूंगा, कटहल करंज, आवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	540
		कुल	2450

11. <u>प्रकरण क्रमांक 9018/2022 – श्री गिर्राज राजोरिया मुडियाखेड़ा, जिला मुरैना (म.प्र.) स्वाईल क्वेरी, खसरा नं. 2206, माइन–2/1, रकबा 1.338 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वाईल क्वेरी –2,000 मी.^{3}, ग्राम देवरी, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण स्वाईल उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 2206, माइन–2/1, रकबा 1.338 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वाईल क्वेरी –2,000 मी.3, ग्राम देवरी, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिर्राज राजोरिया ऑन लाईन/आफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1573 दिनांक 16/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर पूर्व क्षेत्र में 190 मीटर पर आबादी तथा उत्तर दिशा में 240 मीटर पर रोड है । प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बाताया कि ब्लास्टिग प्रस्तावित नही है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन् नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नही की जावेगी । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि
  - ➢ लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ है, जिसे नहीं काटा जायेगा।
  - ➢ लीज क्षेत्र से चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी ।
  - ➢ 02 मीटर गहराई तक ही उत्खनन् किया जावेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/3/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल –2,000 मी.3 प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.90 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख :—

क्रमांक	सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु में
1	ग्राम देवरी के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार का वितरण	30,000/-
2	किसानों को गूगल पेड़ का वितरण और वृक्षारोपण व रखरखाव का प्रशिक्षण	5,000/-
3	ग्राम देवरी में महामारी में सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स के रूप में वितरण और प्रशिक्षण	5,000/-
	Total	**40,000/**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षो का वृक्षारोपण :—

वृक्षारोपण स्थान	पौधों की प्रजातियां	मात्रा
बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि।	**400**
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला, पुत्ररनजीवा, मोलश्री आदि।	**500**
विद्यालय	नीम कचनार, महुआ, अचार अमलतास, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	**50**
ग्राम देवरी के आंगनवाड़ी केंद्र में वितरण हेतु	नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला, पुत्ररनजीवा, गूगल मोलश्री आदि।	**720**
योग		**1600**

12. प्रकरण क्रमांक 9019/2022 – श्रीमती शारदा मीना, ग्राम बोकडी तहसील पिछोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 742, 743, रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 9,690 मी.^{3}, ग्राम बोकडी, तहसील पिछोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 742, 743, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बोकडी, तहसील पिछोर, जिला राजगढ़ . (म.प्र.) पर स्थित है।

557वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2022

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शारदा मीना ऑन लाईन/आफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 135 दिनांक 01/12/2020 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर तथा 220 मीटर पर उत्तर दिशा में पक्का रोड है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में 03 बेर के पेड है जिनको नही काटा जायेगा । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –9690 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.63 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
बोकडी	ग्राम बोकडी स्थित माध्यमिक स्कूल मे पीपी द्वारा एक हैंडपंप (प्रोटेक्शन वाल और रिचार्ज पिट के साथ) लगाया जाएगा I	70,000
	योग	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	संख्या
बैरियर जोन	नीम, जंगल जलेबी ,रीठा , चिरोल , सीताफल , खमेर तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	400
बोकडी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली , आवलाँ सीताफल ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।.	600
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर)	जंगल जलेबी , करंज,कदम ,चिरोल तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	200
	योग	**1200**

13. <u>Case No 9020/2022 M/s Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Shri Rajesh Sharma, Chief General Manager, I/C HSE, Frontier Basins, ONGC, Ganga Building, IDT Campus, Kaulagarh Road, Dist. Dehradun, Uttrakhand Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (5 wells) in OALP-IV Block VN-ONHP-2019/2, Suon Valley, Vindhyan Basin at Village - Gunnor and Amanganj, Tehsil - Gunnor, Dist. Panna (MP)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (5 wells) in OALP-IV Block VN-ONHP-2019/2, Suon Valley, Vindhyan Basin at Village - Gunnor and Amanganj, Tehsil - Gunnor, Dist. Panna (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (5 wells) in OALP-IV Block VN-ONHP-2019/2, Suon Valley, Vindhyan Basin at Village - Gunnor and Amanganj, Tehsil - Gunnor, Dist. Panna (MP) . The project requires prior EC before commencement of any activity at site. The case was presented by the PP wherein following details were submitted that:-

- The exploration Block VN-ONHP-2019/2in Son Valley, Vindhyan Basin, Madhya Pradesh was awarded to ONGC in OALP Bid Round-IV with 100% PI as Operator. RSC was signed on 02.01.2020 and PEL grant deed was signed on 20.11.2020.PEL granted by Govt of Madhya Pradesh for a period of 3 years w.e.f 20.11.2020 to 19.11.2023. In view of COVID-19 pandemic,extension of 101 days granted by MoP&NG/DGH.After extension, the Block validity is: 20.11.2020 to 28.02.2024.

- The acreage comprises approximately 3077.65 sq. km area. It has a Minimum Work Programme of 250 LKM of 2D and 350 SKM of 3D seismic data API and drilling of 12 wells within the specified period of 3 years.
- To pursue the exploratory leads in well Hatta#2 in further strike continuity in eastern part and the leads obtained from recent flow of gas from bore-well at Jhumta in addition to exploration of prospectivity of entire lower Vindhyan Sequence, drilling of about 12 exploratory wells is to be taken up in OALP Block VN-ONHP-2019/2 out of which, 5 are being proposed in based on initial study of existing data. Additional wells will be proposed for drilling based on results obtained from drilling integrated with available data and new 2D and 3D seismic under acquisition. These wells have been planned to explore a number of prospective locale through drilling of vertical wells to target the promising gas reservoirs in the sub-surface.
- The five(5)exploratory locations proposed for Environmental Clearance are located within the state of Madhya Pradesh.All locations lie within the administrative boundaries of Panna district.
- It is expected that the proposed drilling activities in OALPBlock VN-ONHP-2019/2in Madhya Pradesh will lead to the establishment of commerciality and proper assessment of the tight gas reserve potential in this part of Vindhyan Basin. This, in turn, will facilitate firming up of the development strategy for the early monetization of the discovered gas pools and favourably help the country to meet the daunting challenge of ever increasing hydrocarbon demand.
- Exploratory drilling of these wells is temporary and of short duration and includes site preparation, well foundation, rig building, drilling and restoration of the well site. These activities take approximately 6 months per well under normal conditions. Drilling Rig is used which involves rotation of drill bit attached to long string of drill pipes down the well. Water Based Drilling mud is pumped through the string which returns to annulus, this cools the drill bit while cutting and removes the cuttings from the well. The drilling mud is reused as much as possible. At the end of drilling operations, the residual unusable mud is collected in lined pits and solar evaporated.
- The domestic sewage will be treated in septic tanks followed by soak pit system. The solid waste generation is limited to spent drill bits, packaging waste and used containers, drill cuttings and waste oil. The only hazardous waste generated in exploratory drilling operations is spent lube oil. The spent oil will be collected, stored and disposed as per the MoEFCC guidelines and in compliance to the hazardous waste (handling and management) rules. All DG sets will be installed with adequate stack heights to ensure wider dispersion. Emission standards stipulated by CPCB and SPCB would be complied with.

The noise level will not exceed 85 dB beyond the boundary of drill site. Personal protective equipment will be provided and their proper use will be ensured for the protection of workers.

After detail discussion and deliberation, committee asked PP to submit the following information/clarification for further consideration of the project:

1. EMP backup details proposed for different activities.
2. Commitment of PP that all proposed exploratory wells is in non forest area and out of the range of Panna Tiger Reserve Boundary.

PP vide their letter dated 03/03/2022 submitted query reply on Ministry's Parivesh Portal. The query reply was presented by the PP Mr. Amit Kumar Saxena, ONGC and after deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Exploratory Clearance for Exploratory Drilling (5 wells) in OALP-IV Block VN-ONHP-2019/2, Suon Valley, Vindhyan Basin at Village - Gunnor and Amanganj, Tehsil - Gunnor, Dist. Panna (MP) . Category: 1(b) Offshore and Onshore and gas exploration, development & production Project, with following standard conditions:

Statutory compliance:

I. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project. (If applicable)

II. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable. (If applicable)

III. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan/Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the study area) .

IV. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.

V. Necessary authorization required under the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-Boundary Movement) Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016 shall be obtained and the provisions contained in the Rules shall be strictly adhered to.

Air quality monitoring and preservation:

I. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with
II. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines
III. The locations of ambient air quality monitoring stations shall be decided in consultation with the State Pollution Control Board (SPCB) and it shall be ensured that at least one stations each is installed in the upwind and downwind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated.
IV. Ambient air quality shall be monitored at the nearest human settlements as per the National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 for PM‹o, PM2.5, SO2, NOX, CO, CH4. HC, Non-methane HC etc
V. During exploration, production, storage and handling, the fugitive emission of methane, if any, shall be monitored using Infra-red camera/ appropriate technology.
VI. The project proponent also to ensure trapping/storing of the CO2 generated, if any, during the process and handling.
VII. Approach road shall be made pucca to minimize generation of suspended dust.

Water quality monitoring and preservation:

I. As proposed by the project proponent, Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged to any surface water body, sea and/or on land. Domestic sewage shall be disposed off through septic tank/soak pit.
II. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the State Pollution Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
III. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.

IV. The company shall construct the garland drain all around the drilling site to prevent runoff of any oil containing waste into the nearby water bodies. Separate drainage system shall be created for oil contaminated and non-oil contaminated. Effluent shall be properly treated and treated wastewater shall conform to CPCB standards.

V. Drill cuttings separated from drilling fluid shall be adequately washed and disposed in HDPE lined pit. Waste mud shall be tested for hazardous contaminants and disposed according to HWMH Rules, 2016. No effluent/drilling mud/drill cutting shall be discharged/disposed off into nearby surface water bodies. The company shall comply with the guidelines for disposal of solid waste, drill cutting and drilling fluids for onshore drilling operation notified vide GSR.546(E) dated 30 th August, 2005.

VI. ONGC in the process of having a mobile ETP coupled with R.O. on contract basis. The treated 06 KL water used for preparation of mud and water shall be re-cycled and re-used and any excess volume of water left in the waste pits shall be solar evaporated.

Noise monitoring and prevention:

I. The company shall make all arrangements for control of noise from the drilling activity. Acoustic enclosure shall be provided for the DG sets along with the adequate stack height as per CPCB guidelines.

II. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.

III. The ambient noise levels shall conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Act, 1986 Rules, 1989 viz. 75 dBA (day time) and 70 dBA (night time).

Energy Conservation measures:

I. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based

Waste management:

I. Barite waste containing mercury and cadmium shall be analyzed for its hazardous constituents and if exceeds the permissible limits, shall be disposed off in CTSDF or as decided by M. P. Pollution Control Board.

II. Oil spillage prevention and mitigation scheme shall be prepared. In case of oil spillage/ contamination, action plan shall be prepared to clean the site by adopting proven technology. The recyclable waste (oily sludge) and spent oil shall be disposed of to the authorized recyclers.

III. Oil content in the drill cuttings shall be monitored by some Authorized agency and report shall be sent to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India as a part of six monthly compliance reports.

IV. Spent / burnt oil generated is only 500-600 litres per month which is collected in barrels and sent to ONGC's stores of Madhopur, District Gurdaspur, Punjab regularly for disposal to authorized re-cyclers through Metal and Scrap Trading Corporation.

Safety and Human health issues:

I. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

II. Blow-Out Preventer system shall be installed to prevent well blow outs during drilling operations. BOP measures during drilling shall focus on maintaining well bore hydrostatic pressure by proper pre-well planning and drilling fluid logging etc.

III. Company shall prepare operating manual in respect of all activities, which would cover all safety & environment related issues and measures to be taken for protection. One set of environmental manual shall be made available at the drilling site/ project site. Awareness shall be created at each level of the management. All the schedules and results of environmental monitoring shall be available at the project site office. Remote monitoring of site should be done.

IV. On completion of drilling, the company has to plug the drilled wells safely and obtain certificate from environment safety angle from the concerned authority.

V. The company shall take measures after completion of drilling process by well plugging and secured enclosures, decommissioning of rig upon abandonment of the well and drilling site shall be restored the area in original condition. In the event that no economic quantity of hydrocarbon is found a full abandonment plan shall be implemented for the drilling site in accordance with the applicable Indian Petroleum Regulations

VI. The Company shall take necessary measures to prevent fire hazards, containing oil spill and soil remediation as needed. Possibility of using ground flare shall be explored. At the place of ground flaring, the overhead flaring stack with knockout drums shall be installed to minimize gaseous emissions during operation

VII. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

VIII. The company shall develop a contingency plan for H_2S release including all necessary aspects from evacuation to resumption of normal operations. The workers

shall be provided with persona) H2S detectors in locations of high risk of exposure along with self-containing breathing apparatus

IX. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

X. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

XI. The Company shall carry out long term subsidence study by collecting base line data before initiating drilling operation till the project lasts. The data so collected shall be submitted to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India as a part of six monthly compliance.

EMP& CER

I. A budgetary provision of Rs. 6.50 crores is made for Environmental Management Plan as capital cost and Rs 0.5240 crores as recurring cost.

II. PP has proposed following physical targets based Corporate Environment Responsibility (CER).

S.No.	Social Activity	Expenditure in Rupees
1	Saplings of native fruit bearing species will be distributed to nearby villagers (1000 Saplings)	Rs. 40,000.00
2	Medical camps 2 Nos. will be organized	Rs. 8,00,000.00
3	Supplementing Infrastructure in Govt. Schools (05 Nos.)	Rs.15,00,000.00
4	Solar Street Lighting (100 No.)	Rs.15,00,000.00
	Total	**Rs.38,40,000.00**

III. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-1 A.III dated 1s May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

IV. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms /

conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

V. A separate Environmental Cell equipped with full-fledged laboratory facilities shall be set up to carry out the Environmental Management and Monitoring functions, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization,

VI. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the MoEF&CC, Govt. of India along with the Six-Monthly Compliance Report.

VII. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

Miscellaneous

I. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

II. The project proponent shall inform Regional Office as well as MoEF&CC, Govt. of India the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

III. Restoration of the project site shall be carried out satisfactorily and report shall be sent to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India.

IV. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

V. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the PFR report and also that during their presentation to the State Level Expert Appraisal Committee.

VI. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

VII. The MoEF&CC reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

VIII. The Regional Office of the MoEF&CC, Govt. of India shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.

IX. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

14. प्रकरण क्रमांक 9037/2022 – श्री रंजीत सिंह राजपूत, ग्राम जरी, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.) फ्लैग स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 181/2, 181/3, रकबा 1.150 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता, फ्लैग स्टोन – 2,714 मी.^{3}, ग्राम रतनपुर, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण फ्लैग स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 181/2, 181/3, रकबा 1.150 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता, फ्लैग स्टोन – 2,714 मी.3, ग्राम रतनपुर, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.)पर स्थित है।

आज दिनांक 03/03/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रंजीत सिंह राजपूत ऑन लाईन/आफ लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1845 दिनांक 30/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई 02 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 04.23 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण पश्चिम दिशा में 475 मीटर पर कच्चा रोड़ है। प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बाताया कि ब्लास्टिग प्रस्तावित नही है तथा जो पिट लीज एरिया में है वह 2014 के पूर्व से है जबकि मुझे लीज 2021 में स्वीकृत हुई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 03/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन –2714 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.82 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
रतनपुर	ग्राम रतनपुर स्थित आंगनवाड़ी मे पीपी द्वारा 6 माह तक ''पोषण आहार'' का वितरण किया जावेगा I	60,000 /-
	योग	60,000 /-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	संख्या
बैरियर जोन	बरगद , नीम , जंगल जलेबी ,चिरोल , सीताफल , खमेर तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।	300
परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	करंज , कदम ,चिरोल, जंगल जलेबी तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।.	300
रतनपुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली , आवलाँ, सीताफल ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की प्रजातियां आदि।.	800
	योग	1400

15. प्रकरण कमांक 9032/2022 – श्री अब्दुल सलाम, सिविल लाईन, जिला झांसी (उ.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 850/4, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 85,000 मी.^{3}, ग्राम शकुली, तहसील एवं जिला निवाडी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 850/4, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 85,000 मी.3, ग्राम शकुली, तहसील एवं जिला निवाडी (म.प्र) पर स्थित है।

557वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2022

प्रकरण आज दिनांक 03/03/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण एक और अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का समिति निर्णय लेती है फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.

b. Mining Lease area of the project (in ha.)
c. Production capacity of the project.

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
    नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.